International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.882, Volume 05, No. 04(I), October - December, 2023, pp. 100-104

जिले में गरीबी उन्मूलन योजना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भूमिका का अध्ययन

नम्रता दुबे*
डॉ. प्रतिमा बनर्जी**

सार

सार्वजनिक वितरण प्रणाली गरीबी उन्मूलन हेतु उपभोक्ताओं/लाभार्थियों को रियायती कीमतों पर जरूरी उपभोग की सामग्री उपलब्ध करा रही है, जिससे मूल्य बढ़ोत्तरी के प्रभावों से उसे सुरक्षित किया जा सके और जनमानसों में न्यूनतम पोषण की दशा को भी बनाये रखा जा सके। जिले/अध्ययन क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरित किया जाने वाली सामग्रियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीनी, चावल, गेहूँ, मिट्टी का तेल एवं दाल है। इस प्रणाली के खाद्यान्न मुहैया करवाने वाली मुख्य एजेंसी भारतीय खाद्य निगम है। निगम का कार्य अनाज एवं अन्य पदार्थों की खरीद, बिक्री एवं भण्डारण करना है। खाद्य सामग्री क्रय करने में असमर्थता के साथ सामाजिक संरचना भी खाद्य की दृष्टिकोण से असुरक्षा में भूमिका अदा करता है, जिले के गरीब परिवारों के वर्गों की भूमि का आधार कमजोर होता है या उनकी भूमि की उत्पादकता बहुत ही कम होता है। वे खाद्य की दृष्टिकोण से धीघ्र असुरक्षित हो जाते हैं, इन जातियों के लोग खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित होते हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं से काफी प्रभावित है तथा जिन्हें कार्य की खोज में अपनी स्थानीय जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह जाना पड़ता है। ग्रामीण अंचलों की महिलाएं कुपोषण से सबसे अधिक प्रभावित होती है।

शब्दकोशः *सार्वजनिक वितरण प्रणाली, हितग्राही, गरीबी उन्मूलन योजना, खाद्यान्न, उचित मूल्य की दुकान, समाजार्थिक।*

प्रस्तावना

सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा निर्धारित करने की दिशा में सरकार का सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान है। शुरू में यह प्रणाली सभी के हेतु थी तथा गरीबों एवं गैर–गरीबों के मध्य कोई भेद कदापि नहीं की जाती थी, पश्चात् वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सर्वाधिक कुशल एवं अत्यधिक लक्षित बनाने हेतु संशोधित की गयी। वर्ष 1992 में जिले के ब्लाकों में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रारम्भ की गयी। इस प्रणाली का लक्ष्य अध्ययन क्षेत्र के पिछड़े क्षेत्रों एवं कमजोर वर्गों को लाभान्वित करना था। जून 1997 में जिले के समस्त भागों में निवासित निर्धनों को लक्षित करने के सिद्धांत को अपनाने हेतु लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू कियागया। यह पहला अवसर था जब सरकार द्वारा गरीबों एवं गैर–निर्धनों हेतु विभेदक कीमत नीति को स्वीकार किया गया। इनके अतिरिक्त वर्ष 2000 में दो विशिष्ट योजनाएं प्रारम्भ की गयी, जिनमें अंत्योदय अन्न योजना एवं अन्नपूर्णा योजना है। ये योजनाएं सर्वाधिक निर्धनों में भी सबसे अत्यधिक निर्धन तथा कमजोर वर्ग के व्यक्ति समूहों पर केन्द्रित है। इन दोनों योजनाओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा संचालित की जाती है।

---

* शोधार्थी वाणिज्य, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश।
** शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना, मध्य प्रदेश।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली मूल्यों को स्थिर बनाने एवं सामर्थ्य के अनुसार कीमतों/मूल्यों पर उपभोक्ताओं को खाद्यान्न मुहैया करवाने की सरकार की नीति में सबसे अत्यधिक प्रभावी स्रोत साबित हुआ है। इस प्रणाली ने अध्ययन क्षेत्र के अनाज की अधिशेष भागों से कम वाले भागों में खाद्य पूर्ति द्वारा अकाल एवं भुखमरी की व्यापकता पर प्रतिबंध लगाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। इनके अलावा सामान्य रूप में गरीब परिवारों के हितों को ध्यान में रखते हुए कीमतों का संशोधन होता रहा है। कम समर्थित मूल्य/कीमत तथा अधिप्राप्ति द्वारा खाद्यान्नों के उत्पादन की बढ़ोत्तरी में अहम योगदान अदा किया है और जिले के कुछ हिस्सों में कृषकों की आय को सुरक्षा उपलब्ध किया गया है।

शोध उद्देश्य

प्रस्तुत शोध आलेख को निम्न उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्ण करने का सार्थक प्रयास किया गया है, जो क्रमशः इस प्रकार है–

- रीवा जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करना।
- जिले में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा खाद्यान्न वितरण की पूर्ति के स्तर का अध्ययन करना।

उपरोक्त उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए शोध आलेख को पूर्ण किया गया है।

शोध परिकल्पना

किसी भी शोध आलेख को प्रारम्भ करने से पूर्व उससे संबंधित शोधकर्ता के मस्तिष्क में जो प्रारम्भिक विचार उत्पन्न होते हैं उसे परिकल्पना की संज्ञा दी जाती है। इस दृष्टि से शोधकर्ता ने निम्न परिकल्पनाओं को केन्द्र में रखकर शोध आलेख को प्रस्तुत किया गया है, जो क्रमशः इस प्रकार है–

- जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वास्तविक स्थिति एवं खाद्यान्नों के वितरण में संबंध है।
- रीवा जिले में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और इससे लाभान्वित हितग्राहियों की खाद्यान्न आपूर्ति में घनिष्ठ संबंध है।

उपरोक्त परिकल्पनाओं को केन्द्र में रखकर शोध पत्र को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध आलेख में प्रयोग किये जाने वाले तथ्यों को प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से एकत्रित किया गया है। जिसके लिए प्राथमिक समंकों के संकलन हेतु शोधकर्ता द्वारा लोगों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर अनुसूची के माध्यम से मौलिक समंकों को संकलित किया गया है। द्वितीयक समंकों का संकलन शासकीय एवं गैर शासकीय सूचनाओं, पत्र–पत्रिकाओं एवं प्रकाशनों इत्यादि से एकत्रित किये गये हैं। प्राथमिक समंकों को वर्गीकृत कर सारणीयन के पश्चात् विश्लेषणात्मक अध्ययन कर परिणाम प्राप्त किये गये हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में अवलोकन, सर्वेक्षण, निदर्शन, इत्यादि प्रविधियों का भी यथा सम्भव प्रयोग किया गया है।

विश्लेषण

रीवा जिले में गरीबी उन्मूलन परियोजना के लाभान्वित हितग्राहियों का अध्ययन करने के लिए निर्धारित किये गये उद्देश्यों को आधार बनाकर प्राथमिक स्तर पर जिले के 09 विकासखण्डों में से 06 विकासखण्डों– रीवा, रायपुर कर्चुलियान, गंगेव, नईगढ़ी, हनुमना एवं त्योंथर का चयन किया गया है। इन चयनित विकासखण्डों में से 50–50 हितग्राहियों का चयन कर कुल 300 हितग्राहियों से सर्वेक्षण कार्य करते समय अनुसूची के माध्यम से मौलिक तथ्यों का संकलन किया गया है, जिनका विश्लेषणात्मक अध्ययन निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत किया है, जो क्रमशः इस प्रकार है–

- **शोध क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थिति**

रीवा जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वास्तविक स्थिति का आकलन करने हेतु विकासखण्डों से चयन किये गये कुल 300 व्यक्तियों से गरीबी उन्मूलन परियोजना से लाभान्वित हितग्राहियों से सर्वेक्षण का कार्य करते समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थिति का वास्तविक मूल्यांकन करने हेतु अनुसूची के माध्यम से मौलिक तथ्यों को संग्रहित कर तालिका क्रमांक–1 में प्रस्तुत कर विश्लेषण किया गया है जो इस प्रकार है–

तालिका 1: जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थिति का विवरण

क्र.सं.	विवरण	हितग्राहियों से प्राप्त अभिमतों का संग्रहण	
		संख्या	प्रतिशत
1.	बहुत अच्छा	159	53.00
2.	मध्यम अच्छा	65	21.67
3.	सामान्य अच्छा	56	18.67
4.	कुछ कह नहीं सकते	20	6.66
	योग	**300**	**100.00**

स्रोत– प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित।

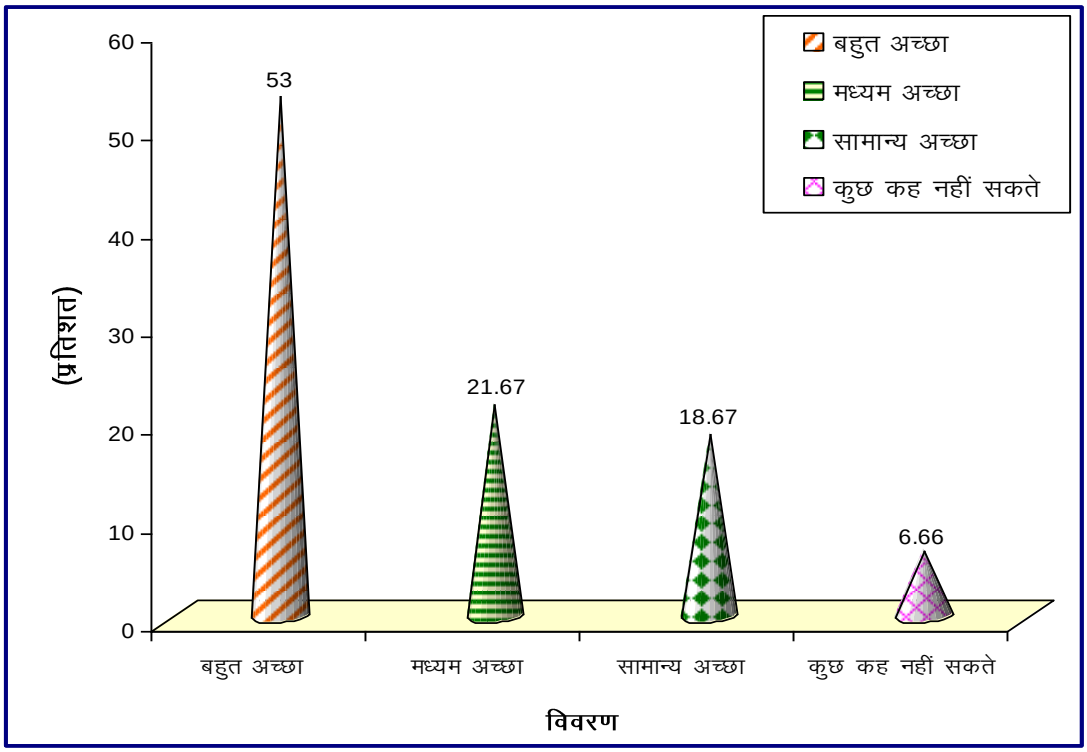

आरेख 1: जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थिति का विवरण

उपर्युक्त तालिका 1 से स्पष्ट होता है कि यह जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थिति के विवरण से संबंधित है, शोधार्थी द्वारा चयन किये गये कुल 300 हितग्राहियों में 159 हितग्राहियों ने स्वीकारा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थिति बहुत अच्छी है जिनका प्रतिशत 53.00 है, 65 हितग्राहियों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दशा मध्यम अच्छा बतलाया जिनका प्रतिशत 21.67 है, 56 हितग्राहियों ने बताया कि प्रणाली की स्थिति सामान्य अच्छी है जिनका प्रतिशत 18.67 है और 20 हितग्राहियों ने बतलाया कि कुछ कह नहीं सकते जिनका प्रतिशत 6.66 है।

- **लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा खाद्यान्न वितरण की पूर्ति का स्तर**

रीवा जिले में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों के वितरण की पूर्ति के स्तरों का आकलन करने के लिए प्राथमिक स्तर सर्वेक्षण का कार्य करते समय अनुसूची का उपयोग कर मौलिक समंकों को संकलित कर वर्गीकरण के साथ तालिका क्रमांक–2 में प्रस्तुत कर विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है जो इस प्रकार है –

तालिका 2: अध्ययन क्षेत्र में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा खाद्यान्न वितरण की पूर्ति का स्तर

क्र.सं.	विवरण	हितग्राहियों से प्राप्त अभिमतों का संग्रहण	
		संख्या	प्रतिशत
1.	बहुत अच्छा	157	52.33
2.	मध्यम अच्छा	66	22.00
3.	सामान्य अच्छा	45	15.00
4.	कुछ कह नहीं सकते	32	10.67
	योग	300	100.00

स्रोत– प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित।

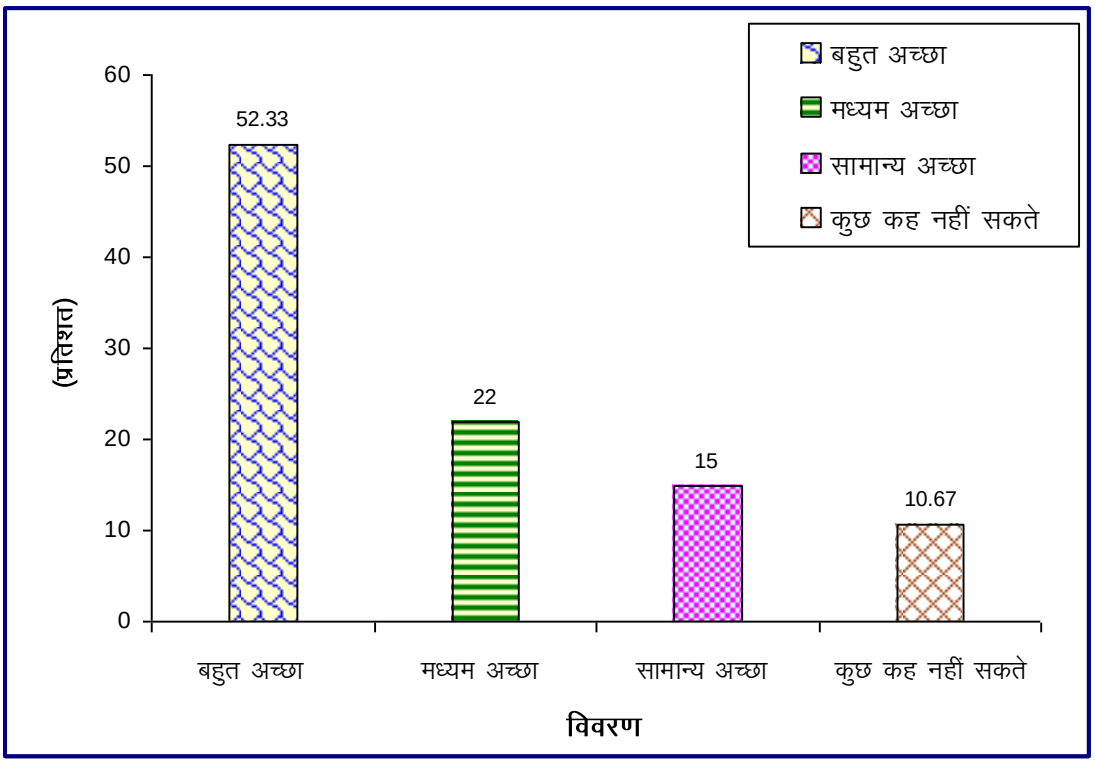

आरेख 2: अध्ययन क्षेत्र में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा खाद्यान्न वितरण की पूर्ति का स्तर

उक्त तालिका 2 से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खद्यान्नों के वितरण की पूर्ति के स्तरों से संबंध है। जिसके लिए चयनित कुल 300 हितग्राहियों में से 157 लोगों ने खद्यान्नों के वितरण की पूर्ति के स्तर को बहुत अच्छा स्वीकार किया है जिसका प्रतिशत 52.33 है। इसी प्रकार 66 लोगों ने मध्यम अच्छा, 45 हितग्राहियों ने सामान्य अच्छा और 32 लाभार्थियों ने कुछ कह नहीं सकते हैं को स्वीकार किया है जिनके प्रतिशत क्रमशः 22.00, 15.00 एवं 10.67 है।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः जिले के सर्वाधिक चयनित हितग्राहियों ने बतलाया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दशा बहुत अच्छी है। जिले में इस प्रणाली के माध्यम से हितग्राहियों को आवश्यक सामग्री की उपलब्धता सस्ते कीमत पर होती है, जिससे उनकी आय पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अतएव रीवा जिले में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा खाद्य सामग्रियों के वितरण की पूर्ति का स्तर बहुत अचदा है जिससे जिले के गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करने वाले लोगों का कल्याण हो रहा है और इससे अध्ययन क्षेत्र से गरीबी का धीरे–धीरे समापन हो रहा है, जिसके वजह से रीवा जिला विकास के पथ पर अग्रसर होता जा रहा है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. दत्त, रूद्ध एवं सुन्दरम् के.पी.एम. – भारतीय अर्थव्यवस्था, एस. चन्द्र एण्ड कम्पनी लि., वर्ष 2015
2. शर्मा, जैन पारीक – शोध प्रणाली एवं सांख्यिकीय तकनीक, रमेश बुक डिपो, जयपुर, वर्ष 2008
3. सिंह, डॉ. सुदामा – भारतीय अर्थव्यवस्था समस्याएं नीतियां, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, वर्ष 1994
4. शर्मा, ए.के. – मजदूर नीति तथा सामाजिक सुरक्षा, ओमेगा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, वर्ष 2010
5. चतुर्वेदी, विनायक – ग्रामीण विकास, प्रिज्म बुक्स, जयपुर, वर्ष 2011
6. गुप्ता, यू.सी. एवं मित्तल आभा – सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं ग्रामीण निर्धनता, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, वर्ष 2014
7. कानवा, योगेश एवं कटारिया, सुरेन्द्र – भारत में निर्धनता, आर्थिक विकास एवं मीडिया, आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, जयपुर, वर्ष 2006

❖◆❖